Think
IAS...

दृष्टि
The Vision

Think
Drishti

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

समसामयिक घटनाक्रम

(बिहार के विशेष संदर्भ सहित)

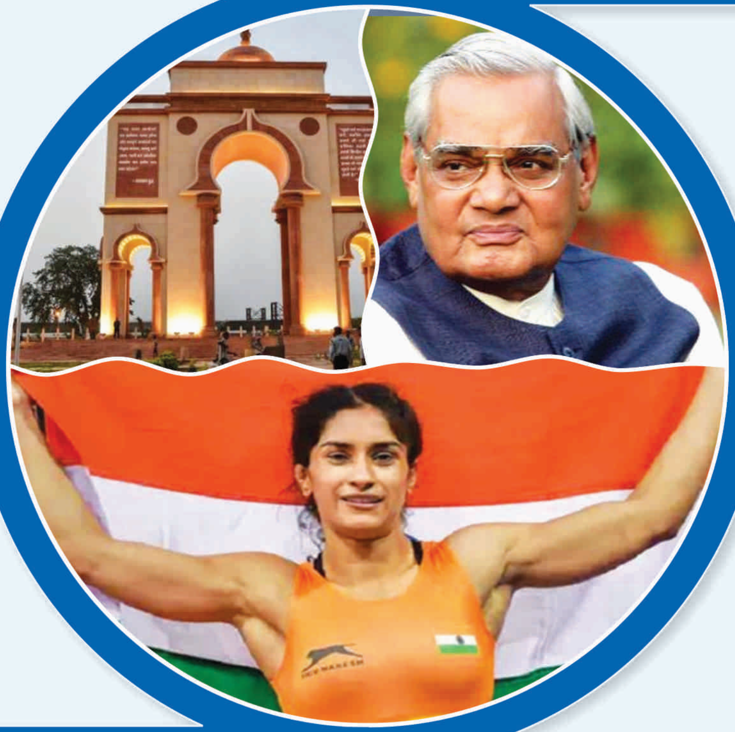

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम *(Distance Learning Programme)*

Code: BRPM22

बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC)

समसामयिक घटनाक्रम

(बिहार के विशेष संदर्भ सहित)

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 011-47532596, 87501 87501
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

BPSC DLP

विषय सूची (Contents)

1.	संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम	5–74
2.	आर्थिक परिदृश्य	75–134
3.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे	135–153
4.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	154–170
5.	पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी	171–187
6.	सुरक्षा	188–199
7.	सामाजिक मुद्दे	200–214
8.	कला एवं संस्कृति	215–221
9.	खेल घटनाक्रम	222–229
10.	बिहार सम-सामयिकी	230–233
11.	विविध	234–248

अध्याय
1

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम
(Constitutional/Administrative Development)

केंद्र ने केरल की बाढ़ को 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित किया

चर्चा में क्यों?

केरल में बाढ़ की भयावह स्थिति को देखते हुए भारत सरकार ने इसे 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित किया है, जिससे विभिन्न रूपों में राष्ट्रीय सहायता का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- गृह मंत्रालय ने कहा है कि वर्ष 2018 में केरल में आई बाढ़/भूस्खलन की तीव्रता और परिमाण को ध्यान में रखते हुए यह सभी दृष्टिकोण से 'गंभीर प्रकृति की आपदा' है।
- उल्लेखनीय है कि यह वर्गीकरण राज्य को केंद्र से अधिक मौद्रिक और अन्य सहायता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।
- केरल में आई बाढ़ की विभीषिका को देखें तो 8 अगस्त से 223 लोगों ने अपनी जान गँवा दी है।
- इसके अलावा 2.12 लाख महिलाओं और 12 साल से कम उम्र के एक लाख बच्चों सहित 10.78 लाख विस्थापित लोगों को 3,200 राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है।
- प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार, राज्य को अब तक लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हालाँकि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य को हरसंभव सहायता प्रदान की है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) समूह के प्रतिनिधियों द्वारा कम समय में राहत और बचाव सामग्री की सुविधाएँ सुनिश्चित की जाएंगी।
- एनडीएमए के अधिकारियों ने कहा कि केंद्र और आसपास के राज्यों की सहायता से मेडिकल टीमों को केरल भेज दिया गया है, जो किसी भी महामारी को रोकने में मदद करेंगी।

'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित करने के लाभ

- जब एक आपदा 'दुर्लभ गंभीरता'/'गंभीर प्रकृति' के रूप में घोषित की जाती है तो राज्य सरकार को राष्ट्रीय स्तर का समर्थन प्रदान किया जाता है।
- इसके अतिरिक्त केंद्र एनडीआरएफ की सहायता भी प्रदान कर सकता है।
- आपदा राहत निधि (सीआरएफ) को स्थापित किया जा सकता है, यह कोष केंद्र और राज्य के बीच 3 : 1 के साझा योगदान पर आधारित होता है।
- इसके अलावा सीआरएफ में संसाधनों के अपर्याप्त होने की अवस्था में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि (एनसीसीएफ) से अतिरिक्त सहायता दिये जाने पर भी विचार किया जाता है, जो केंद्र द्वारा 100% वित्तपोषित होती है।
- गौरतलब है कि संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (MPLADS) के दिशा-निर्देशों के पैराग्राफ 2.8 में कहा गया है- 'देश के किसी भाग में गंभीर आपदा की स्थिति में सांसद सदस्य प्रभावित ज़िले के लिये अधिकतम एक करोड़ रुपए तक के कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं।'
- दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि जिस दिन से संसद सदस्य इस प्रकार का योगदान करेंगे, उसी दिन से संबंधित अधिकारी को एक महीने के अंदर राहत कार्यों को चिह्नित करना होगा और इस पर आठ महीने के अंदर अमल करना होगा।

आगे की राह

- मिज़ो शांति समझौते के अस्तित्व में आने के बाद मिज़ोरम ने राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। वर्तमान जनगणना (2011) के आँकड़ों के अनुसार मिज़ोरम भारत का ***तीसरा सर्वाधिक साक्षर*** (91.58%) राज्य है।
- अभी हाल ही में (मई 2017) मिज़ोरम शांति समझौते के पुनरीक्षण के लिये राज्यपाल निर्भय शर्मा ने एक समिति की नियुक्ति की है। इस समिति में मिज़ोरम के सभी आदिवासी समूहों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। यह समिति शांति समझौते के प्रावधानों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आवश्यक संशोधन की संस्तुति करेगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना

- केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लिये निजी ज़मीन पर सस्ते घरों के निर्माण को मंज़ूरी दी है। योजना के अनुसार ***महाराष्ट्र के शोलापुर ज़िले*** में 30,000 सस्ते घर बनाए जाने हैं।
- यह पहली बार है जब ***प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)*** की किफायती आवास परियोजना (अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट) के लिये निजी ज़मीन का उपयोग किया जाएगा।
- इससे पहले अनुमोदित परियोजनाएँ राज्य सरकार या नगर निगमों से संबंधित सरकारी भूमि पर क्रियान्वित होती थीं।
- आवासन तथा शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव के अधीन अंतर-मंत्रालयीय केंद्रीय स्वीकृति तथा निगरानी समिति (इंटरमिनिस्टीरियल सेंट्रल सैंक्सनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी) ने इस योजना को मंज़ूरी दी है।
- राज्यस्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (स्टेट लेवल सैंक्सनिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी) परियोजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी।
- इस परियोजना को मंज़ूरी मिलने के पश्चात् भविष्य में और भी ऐसी योजनाओं को बल मिलेगा जिनमें ***निजी भूमि का उपयोग किया जा सकेगा***।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

- योजना का लक्ष्य ***2022 तक सभी शहरी गरीबों को आवास*** प्रदान करने का है। इस उद्देश्य से पूरे देश में ***2 करोड़ घरों के निर्माण*** की योजना है।
- इसके लिये 4041 वैधानिक कस्बों में से 500 श्रेणी-I के शहरों पर शुरुआती ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इनका क्रियान्वयन तीन फेज़ में किये जाने की योजना है–

फेज I – 100 शहर – (अप्रैल 2015 - मार्च 2017)
फेज II – 200 शहर – (अप्रैल 2017 - मार्च 2019)
फेज III – शेष शहर – (अप्रैल 2019 - मार्च 2022)

- यह योजना झुग्गी-झोपड़ी निवासियों के लिये निजी डेवलपर्स के सहयोग से पुनर्वासन, किफायती घरों के लिये सब्सिडी युक्त ब्याज वाले दीर्घकालिक ऋण (निम्न तथा मध्यम आय समूहों) तथा निजी सरकारी सहयोग जैसे विभिन्न मॉडलों का उपयोग करती है।
- योजना के तहत निर्मित घर, परिवार की महिला प्रमुखों अथवा पुरुष तथा उसकी पत्नी दोनों के नाम पर संयुक्त रूप से आवंटित किया जाएगा।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- हाल ही में केंद्र सरकार ने केरल में बाढ़ की स्थिति को 'गंभीर प्रकृति की आपदा' घोषित किया है।
- देश में सबसे अच्छे तरीके से शासित प्रदेशों की सूची में केरल शीर्षस्थ राज्य है।

- वैश्विक रियल स्टेट पारदर्शिता सूचकांक में भारत 35वें स्थान पर है।
- सवर्ण रेखा बंदरगाह ओडिशा के बालासोर ज़िले में निर्मित हो रही है।
- राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 68% ग्रामीण परिवार शौचालय का इस्तेमाल करते हैं।
- चंपारण सत्याग्रह की याद में चंपारण से ही 'सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह' अभियान चलाया गया।
- 'स्फूर्ति एप्प' का संबंध रेल यातायात से है।
- संचार मंत्रालय द्वारा सेवा गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से 'दर्पण' एप शुरू किया गया है।
- दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध डाक टिकट संग्रहण से है।

बहुविकल्पीय प्रश्न

1. उत्तर कोयल जलाशय परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है?
(a) बिहार तथा उत्तर प्रदेश
(b) झारखंड तथा पश्चिम बंगाल
(c) बिहार तथा झारखंड
(d) उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड

2. भारतीय प्रतिभूति एवं विनियमय बोर्ड (सेबी) ने उचित बाज़ार आचरण पर कौन-सी समिति गठित की है?
(a) विश्वनाथन समिति (b) दीपक पारेख समिति
(c) संथामन समिति (d) उर्जित पटेल समिति

3. निम्नलिखित में से कौन-सी सस्ते दर पर एलईडी बल्ब के वितरण की विश्व की सबसे बड़ी योजना है?
(a) उज्ज्वला योजना (b) उजाला योजना
(c) कुसुम योजना (d) सौर सुजला योजना

4. हाल ही में भारत सरकार ने किस देश की सहायता हेतु 'ऑपरेशन इंसानियत' का शुभारंभ किया?
(a) अफगानिस्तान (b) नेपाल
(c) बांग्लादेश (d) श्रीलंका

5. हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस शहर में राष्ट्रव्यापी स्वच्छता अभियान 'स्वच्छता ही सेवा' का शुभारंभ किया?
(a) पटना (b) कानपुर
(c) मुजफ्फरपुर (d) नई दिल्ली

6. ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस-2018 में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त है?
(a) 100वाँ (b) 130वाँ
(c) 122वाँ (d) 97वाँ

7. हाल ही में किस बीमारी को 2030 तक समाप्त करने हेतु 'मिशन संपर्क' के आरंभ की घोषणा की गई है?
(a) पोलियो (b) मलेरिया
(c) एड्स (d) इबोला

8. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार पर वैश्विक सूचकांक-2017 (Corruption Perception Index-2017) के अनुसार सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश कौन से हैं?
(a) भारत (b) स्वीडन
(c) फिनलैंड (d) न्यूज़ीलैंड

9. राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण (NARSS) 2017-18 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय का इस्तेमाल करते हैं?
(a) 50% (b) 68%
(c) 93% (d) 74%

10. हाल ही में भारत के प्रतिस्पर्द्धा आयोग के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन किया गया है। अब इस आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होंगे?
(a) चार (b) सात
(c) छः (d) दस

11. हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा गठित 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
(a) डॉ. अशोक लाहिड़ी (b) डॉ. रमेश चंद
(c) एन.के. सिंह (d) अरविंद मेहता

12. भारत युवा विकास सूचकांक एवं रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है?
(a) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरांबुर
(b) मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(c) आईआईएम, अहमदाबाद
(d) आईआईटी, दिल्ली

13. हाल ही में प्रारंभ 'सौभाग्य योजना' का मुख्य उद्देश्य क्या है?
    (a) सभी महिलाओं को नि:शुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करना।
    (b) सभी घरों को बिजली प्रदान करना।
    (c) ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन का वितरण करना।
    (d) युवाओं को स्वरोजगार हेतु कौशल प्रदान करना।
14. हाल ही में जारी वैश्विक भुखमरी सूचकांक-2017 में भारत को कौन-सा स्थान प्राप्त है?
    (a) 97वाँ
    (b) 100वाँ
    (c) 163वाँ
    (d) 133वाँ
15. हाल ही में न्यायमूर्ति राजेश बिंदल समिति ने किस विषय पर अपनी सिफारिशें सौंपी हैं?
    (a) बच्चों के अंतर्देशीय निष्कासन और पुनर्स्थापना
    (b) सुधार गृहों में बच्चों की सुरक्षा।
    (c) स्कूलों में बालिकाओं की सुरक्षा।
    (d) स्कूल जाने वाले बच्चों के स्कूल बैग के बोझ को कम करना।

उत्तरमाला

1. (c)	2. (a)	3. (b)	4. (c)	5. (b)	6. (b)	7. (c)	8. (d)	9. (b)	10. (a)
11. (c)	12. (a)	13. (b)	14. (b)	15. (a)					

दीर्घउत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर से आप क्या समझते हैं? हाल ही में यह क्यों चर्चित रहा है? इस संदर्भ में असम समझौता पर प्रकाश डालिये। साथ ही यह स्पष्ट कीजिये कि क्या इससे भारत में नागरिकता संबंधी विवाद उत्पन्न हो सकता है? उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत कीजिये।
2. 'मॉब लिंचिंग' से क्या तात्पर्य है? हाल ही में घटित घटनाओं का उल्लेख कीजिये। इस संदर्भ में सरकार, न्यायालय तथा आम जनता की भूमिका पर उचित सुझाव प्रस्तुत कीजिये।
3. भारतीय लोकतंत्र में 'एक साथ चुनाव' का क्या निहितार्थ है? एक साथ चुनाव कराने हेतु पक्ष एवं विपक्ष की तुलना करते हुए अपना मत स्पष्ट कीजिये।
4. कावेरी जल विवाद क्यों चर्चित रहा है? इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को उल्लेख कीजिये। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान निर्णय को स्पष्ट कीजिये।

अध्याय
2

आर्थिक परिदृश्य
(Economic Scenario)

भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार

रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) द्वारा एक्सचेंज मैनेजमेंट पर जारी छमाही रिपोर्ट के अनुसार, भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार कमी हो रही है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- विदेशी मुद्रा भंडार से संबंधित रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले 10 महीनों में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आई है।
- आँकडों के अनुसार, 29 जून, 2018 को विदेशी मुद्रा भंडार 406.05 बिलियन डॉलर था, जबकि उससे पूर्व सप्ताह में 22 जून, 2018 को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 407.81 बिलियन डॉलर था।
- अल्पावधि ऋण में विदेशी मुद्रा भंडार का अनुपात जो कि मार्च 2017 के अंत में 23.8% था, दिसंबर 2017 के अंत में भी उसी स्तर पर बना रहा।
- रिज़र्व बैंक के पास 560.32 टन स्वर्ण भंडार है, जिसमें से 268.01 टन स्वर्ण बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स (BIS) के पास सुरक्षित है।
- वहीं, 399.44 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में से 262.01 बिलियन डॉलर प्रतिभूतियों में निवेश किये गए थे, अन्य केंद्रीय बैंकों और BIS में 109.67 बिलियन डॉलर जमा किये गए थे और वाणिज्यिक बैंकों में 27.76 बिलियन डॉलर जमा थे।

ट्राई का सार्वजनिक वाई-फाई मॉडल

दूरसंचार ऑपरेटरों ने क्षेत्रीय नियामक ट्राई द्वारा अनुशंसित सार्वजनिक वाई-फाई मॉडल का विरोध किया है। इन ऑपरेटरों का कहना है कि इससे कर्ज़ में डूबे उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने जैसा होगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India – TRAI) ने साइबर कैफे के मौजूदा नियमों की तर्ज़ पर पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर (Pubic Data Office Aggregator – PDOA) के लिये सिफारिश की है।
- सिफारिशों में कहा गया है कि जिस प्रकार साइबर कैफे पंजीकरण के पश्चात् इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करते हैं, वैसे ही PDOA को दूरसंचार विभाग में पंजीकरण के बाद वाई-फाई इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने की अनुमति दी जाए।
- PDOA के रूप में नई कंपनियाँ पिछले दौर के PCO की तरह ही पब्लिक डाटा ऑफिस (Public Data Office – PDO) खोल सकेंगी।
- इस संबंध में मोबाइल कंपनियों के शीर्ष संगठन सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Cellular Operators Association of India– COAI) का कहना है कि लाइसेंस के बिना इंटरनेट सेवाएँ बेचने के प्रस्ताव का अर्थ मौजूदा लाइसेंसिंग व्यवस्था को पूरी तरह अनदेखा करना होगा।
- COAI के अनुसार, ये सिफारिशें स्पेक्ट्रम और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश करने वाली टेलीकॉम कंपनियों के लिये नुकसानदायक हैं तथा इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है।
- उल्लेखनीय है कि COAI अप्रैल 2017 से ही पब्लिक वाई-फाई सेवाओं के मामले में TRAI के सुझावों का विरोध कर रही है।

अध्याय
3

अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे
(International Issues)

FATF की 10–बिंदु योजना

फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) ने प्रतिबंधित आतंकी संगठनों की फंडिंग के खिलाफ ठोस कार्रवाई में नाकाम रहने के कारण पाकिस्तान को निगरानी सूची (ग्रे–लिस्ट) में रखने के संबंध में फरवरी में लिये गए अपने फैसले को सर्वसम्मति से लागू करने की सहमति व्यक्त की है। इसके दिशा–निर्देशों के अनुपालन के लिये 10–बिंदुओं की कार्य–योजना तैयार की गई है। उल्लेखनीय है कि फरवरी में आयोजित बैठक में पाकिस्तान को निगरानी सूची में शामिल करते हुए आतंकी फंडिंग रोकने के लिये ज़रूरी कदम उठाने की चेतावनी दी गई थी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- आतंकवाद के खिलाफ विस्तृत कार्य–योजना को लागू करने में पाकिस्तान की विफलता के परिणामस्वरूप अगले वर्ष इसे ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा सकता है।
- पाकिस्तान को दूसरी बार ग्रे–सूची में सूचीबद्ध किया गया है तथा उसे यह निर्देश दिया गया है कि वह संयुक्त राष्ट्र द्वारा नामित आतंकवादियों यथा–हफीज सईद और मसूद अजहर की आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाए। साथ ही तालिबान और हक्कानी नेटवर्क, जैश–ए–मोहम्मद, लश्कर–ए–तैयबा और उनके सहयोगी आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाए तथा उनके फंडिंग के स्रोतों को बंद करे।

कनाडा में वैध हुआ मारिजुआना

दिसंबर 2013 में उरुग्वे ने मारिजुआना के उत्पादन, बिक्री और खपत को वैध किया था। इसके बाद अब कनाडा में भी मारिजुआना को वैध बनाने संबंधी विधेयक को पारित किया गया है। 17 अक्तूबर, 2018 से कनाडा में मारिजुआना का इस्तेमाल वैध होगा। इस निर्णय के पीछे सरकार का मकसद संगठित अपराधों में कमी लाते हुए देश के युवाओं को सुरक्षित करना है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- कुछ देशों में यह वैध है तथा इसका इस्तेमाल दवा के रूप में किया जाता है। हालाँकि, विशेषज्ञों का मानना है कि इसके एक सीमा से अधिक इस्तेमाल से यह मस्तिष्क को प्रभावित करता है।
- आईक्यू लेवल को कम कर देता है, मानसिक बीमारी को बढ़ा सकता है तथा लंग्स कैंसर का खतरा भी उत्पन्न कर सकता है।

सऊदी अरब में गाड़ी चला सकेंगी महिलाएँ

24 जून, 2018 को एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में सऊदी अरब में महिलाओं को आधिकारिक तौर पर ड्राइविंग करने (गाड़ी चलाने) का अधिकार प्रदान किया गया। इसके साथ ही यह महिलाओं के गाड़ी चलाने पर लगे प्रतिबंध को हटाने वाला दुनिया का अंतिम राष्ट्र बन गया। अभी तक यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश था, जहाँ महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं थीं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- उल्लेखनीय है कि सितंबर 2017 में ही इस प्रतिबंध को हटाने संबंधी घोषणा की गई थी। इस निर्णय को क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विज़न 2030 कार्यक्रम के एक अहम हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।
- क्राउन प्रिंस का लक्ष्य वर्ष 2030 तक कच्चे तेल के उत्पादन पर निर्भर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को तेल के व्यवसाय से अलग विकसित करना हैं तथा इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बहुत से प्रयास किये जा रहे हैं।

अध्याय 4

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (Science and Technology)

'रिमूव डिब्रीज़'

हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने अंतरिक्ष में फैले रॉकेटों और उपग्रहों के टुकड़ों को हटाने के लिये रिमूव डिब्रीज़ (Remove DEBRIS) नामक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया।

- 100 किलोग्राम वज़न वाले इस स्पेसक्राफ्ट का निर्माण एयरबस की सहायक 'सरे सेटेलाइट टेक्नोलॉजी' द्वारा किया गया है।
- यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से छोड़ा जाने वाला सबसे बड़ा स्पेसक्राफ्ट है।
- अंतरिक्ष में फैले कचरे को हटाने के लिये इस स्पेसक्राफ्ट में तीन एयरबस प्रौद्योगिकियों का प्रयोग किया गया है।
- यह परियोजना वैश्विक/यूरोपीय ADR (Active Debris Removal) रोडमैप में योगदान देने के उद्देश्य पर आधारित है।

जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप

बृहस्पति (Jupiter) पर देखे गए लाल रंग के विशाल धब्बे (Great Red Spot) का अध्ययन करने के लिये नासा के अत्याधुनिक टेलीस्कोप 'जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप' (JWST) का प्रयोग किया जाएगा।

- जेम्स वेब टेलीस्कोप के निर्माणकर्त्ता वैज्ञानिकों द्वारा इस दूरबीन के लक्ष्यों में बृहस्पति के विचित्र तूफानों को भी शामिल किया गया है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा वेब टेलीस्कोप की सहायता से बृहस्पति ग्रह के विशालकाय लाल रंग के धब्बे का मल्टीस्पेक्ट्रल नक्शा तैयार किया जा सकेगा, साथ ही उसकी तापीय, रासायनिक एवं बादल संरचनाओं का विश्लेषण करने में भी मदद मिलेगी।
- वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप की मदद से इंफ्रारेड तरंगदैर्ध्यों का पर्यवेक्षण करने में सक्षम होंगे जिससे यह ज्ञात हो सकेगा कि बृहस्पति के धब्बे का रंग लाल क्यों है।

पृष्ठभूमि

JWST विश्व की सर्वाधिक उन्नत अंतरिक्ष वेधशाला है। पहले इसे NGST (New Generation Space Telescope) के नाम से जाना जाता था, परंतु, सितंबर 2002 में इसका नाम बदलकर नासा के पूर्व व्यवस्थापक जेम्स वेब के नाम पर JWST कर दिया गया। इसका निर्माण ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी रहस्यों को सुलझाने के उद्देश्य से किया गया है।

हायाबुसा-2

जापानी एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने जीवन की उत्पत्ति के रहस्य से पर्दा उठाने हेतु जानकारी एकत्र करने के लिये दिसंबर 2014 में हायाबुसा-2 नामक एक अभियान लॉन्च किया था, जो कि साढ़े तीन साल की यात्रा के बाद पृथ्वी से 30 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित क्षुद्रग्रह 'रायगु' (वैज्ञानिक नाम 162173 JU3) पर पहुँच गया है। इस अभियान का संचालन छह वर्षों के लिये किया जाएगा। इसका नाम फाल्कन पक्षी के नाम पर रखा गया है जिसे जापानी भाषा में हायाबुसा कहा जाता है।

शोधकर्त्ताओं के अनुसार, सौरमंडल के विकास के शुरुआती चरण में ही क्षुद्रग्रह का निर्माण हो गया था। इसी आधार पर उन्होंने 'रायगु' पर जैविक पदार्थ, पानी और जीवन की उत्पत्ति के लिये ज़रूरी मूलभूत तत्त्वों के बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने की संभावना व्यक्त की है।

हायाबुसा-2 की विशेषताएँ

- हायाबुसा-2 में गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम के अलावा एल्टीट्यूड कंट्रोल सिस्टम लगा है।
- सबसे पहले हायाबुसा-2 'रायगु' से 20 किलोमीटर ऊपर रहकर उसका चक्कर लगाएगा और सतह पर उतरने से पहले उसका नक्शा तैयार करेगा।

अध्याय

5

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी
(Environment and Ecology)

पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना

हाल ही में पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई योजना (The Pattiseema Lift Irrigation Scheme) के अंतर्गत 24 पंपों में से 16 को चालू किया गया है।

- यह सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी के अधिशेष जल को कृष्णा नदी की ओर प्रवाहित करने के लिये तैयार की गई है और इसके लिये दोनों नदियों को आपस में जोड़ना आवश्यक है।
- उल्लेखनीय है कि पट्टीसीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पोलवारम की दाईं नहर के द्वारा गोदावरी और कृष्णा नदियों को जोड़ा गया है।
- यह पहल कृष्णा डेल्टा को पुनर्जीवित करने में मदद करेगी जो पूरी तरह से सूख गई है।

'सतत् विकास जल 2018-28' सम्मेलन

केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण तथा जहाज़रानी मंत्री श्री नितिन गडकरी ने **'कार्रवाई के लिये अंतर्राष्ट्रीय दशक : सतत् विकास के लिये जल 2018-28'** विषय पर 20-21 जून, 2018 को ताजिकिस्तान में आयोजित सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किया।

संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत् विकास लक्ष्यों से संबंधित महत्त्वपूर्ण जल विषय पर विचार-विमर्श करने के लिये इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त रूप से संयुक्त राष्ट्र और ताजिकिस्तान गणराज्य की सरकार द्वारा किया गया।

महत्त्व

- भारत के विस्तारित पड़ोस में ताजिकिस्तान रणनीतिक साझेदार देश है। ताजिकिस्तान ने जल संबंधी वैश्विक विषयों पर अग्रणी भूमिका निभाई है।
- जल, सतत् विकास एवं गरीबी उन्मूलन से संबंधित तत्त्व है। यह भोजन, ऊर्जा एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की कुंजी है। इसलिये यह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल को एसडीजी 1,2,3,5,6,7,11,13 एवं 14 सहित कई सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में शामिल किया गया है।
- भारत और ताजिकिस्तान ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति के लिये प्रतिबद्धता की पुन: पुष्टि की और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने में विशेषत: सतत् जल विकास पर सहमति व्यक्त की है।

इस दिशा में भारत के प्रयास

- भारत ने देश के मानचित्र निर्माण योग्य क्षेत्र के दो मिलियन वर्ग किलोमीटर के संपूर्ण मानचित्रण के लिये एक महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रीय जलभृत प्रबंधन परियोजना आरंभ की है।
- नदी संरक्षण के क्षेत्र में नमामि गंगे, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने तथा उसे पुनर्जीवित करने की भारत की प्रमुख योजना है। इसके साथ-साथ दूसरी नदियों के कायाकल्प के लिये भी ऐसे ही कदम उठाए जा रहे हैं जिनसे कि नदियों को उनके मूल रूप में लाया जा सके।
- (प्रधानमंत्री सिंचाई परियोजना) के तहत दिसंबर 2019 तक 99 बड़ी सिंचाई परियोजनाएँ पूरी करने का लक्ष्य तय किया गया है, जिनसे 7.62 मिलियन हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन हो सकेगा।
- इस कार्यक्रम के अन्य महत्त्वपूर्ण उद्देश्य हैं- 'हर खेत को पानी' या कमान क्षेत्र विकास को विस्तारित करना और जल प्रबंधन कार्य आरंभ करना जिनके द्वारा प्रत्येक खेत को जल उपलब्ध कराना है।

अध्याय
6

सुरक्षा
(Security)

रिमपैक नौसेना अभ्यास

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा हवाई द्वीप में आयोजित किये जाने वाले ***प्रशांत महासागरीय नौसेना अभ्यास 'रिम'*** में ***चीन को न शामिल करने का निर्णय लिया गया है।***
- इस वर्ष इस युद्धाभ्यास में ***ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चिली, कोलम्बिया, फ्राँस, जापान तथा भारत*** सहित लगभग ***26 देशों की*** सेनाओं ने भाग लिया।
- इस नौसेना अभ्यास में चीन को आमंत्रित न किये जाने के निर्णय के पीछे मूल कारण उसके द्वारा दक्षिणी चीन सागर में संचालित की गई गतिविधियाँ हैं।
- इस युद्धाभ्यास का आयोजन ***27 जून से 2 अगस्त*** के मध्य किया गया।
- इस युद्धभ्यास में इस वर्ष ***भारत ने*** भी हिस्सा लिया।
- इस वर्ष की थीम ***"Cabable, Adaptive, Partners"*** हैं

पृष्ठभूमि

- ***वर्ष 2014 में चीन ने पहली बार रिमपैक (RIMPAC) नौसेना अभ्यास में भाग लिया*** था।
- इस दौरान चीन की सहभागिता की न केवल सराहना ही की गई बल्कि इसे सहयोग के एक नए कदम के रूप में भी देखा गया था।
- गर्मी के महीनों से ***दक्षिणी तथा पूर्वी चीन*** सागर दोनों के मध्य ***तनाव में वृद्धि*** हो रही है, जिसका प्रमुख कारण ***मछली पकड़ने और व्यापार संबंधी कार्यों की वजह से*** इन सागरों में बढ़ती गतिविधियाँ हैं।

रिमपैक क्या है?

- यह विश्व का बहुत बड़ा ***अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास*** है।
- इसका आयोजन ***प्रत्येक दो वर्षों*** में किया जाता है।
- इसे ***संयुक्त राष्ट्र नौसेना के प्रशांत बेड़े*** (U.S. Navy's Pacific Fleet), जिसका ***मुख्यालय होनोलुलु, हवाई में है, के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है।***
- इसे प्रशांत महासागर में उपस्थित ***रिम राष्ट्रों*** के लिये एक ***अद्वितीय अवसर*** के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि यह इन क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाली समस्याओं के समाधान के लिये न केवल सहभागी राष्ट्रों को ट्रेंड करता है बल्कि साथ मिलकर कार्य करने को प्रोत्साहित भी करता है।
- इस नौसेना अभ्यास को एक ***शक्ति प्रदर्शन के रूप में*** भी देखा जा सकता है, जो कि ***सहभागी देशों की तकनीकी को आपस में समझने और आक्रामक कार्रवाइयों के निवारण में सक्षम बनाता*** है।
- ***रूस, फिलीपीन्स, मेक्सिको, इक्वाडोर तथा चीन*** सहित कई ***पर्यवेक्षक राष्ट्रों*** को आमंत्रित किया जाता है।

S-400 ट्रायम्फ

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में भारत ने अपनी ***वायुसेना*** (Indian Air Force-IAF) के लिये रूस की ***S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस मिसाइल*** प्रणाली को खरीदने के लिये रूस के साथ इसकी कीमत पर की गई वार्ता का निष्कर्ष निकाला है।

अध्याय
7

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट

- शिक्षा प्रणाली अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी, तनाव-युक्त और परीक्षोन्मुख हो गई है, परिणामस्वरूप बच्चे अवसाद और गंभीर मानसिक बीमारियों से ग्रस्त होते जा रहे हैं। यूनेस्को भी इस धारणा को बढ़ावा देता है कि विद्यालयों को सीखने के लिये अनुकूल माहौल प्रदान करना चाहिये, जहाँ बच्चे स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करें।
- इसी आधार पर बैंकॉक स्थित यूनेस्को के 'एशिया-पैसिफिक रीज़नल ब्यूरो फॉर एजुकेशन' ने शिक्षार्थी कल्याण और समग्र विकास के माध्यम से विद्यालयों में खुशी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 'हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट' (Happy Schools Project) लॉन्च किया है।
- यूनेस्को, शांति और सतत् विकास के लिये महात्मा गांधी शिक्षा संस्थान (MGIEP) की भागीदारी से 'हैप्पी स्कूल' के ढाँचे को परिचालित करने की प्रक्रिया में है।

हैप्पी स्कूल प्रोजेक्ट

- MGIEP एशिया-प्रशांत क्षेत्र में यूनेस्को का अपनी तरह का पहला संस्थान है, जिसे भारत सरकार द्वारा समर्थन प्राप्त है।
- इस योजना के अंतर्गत सामाजिक और भावनात्मक अधिगम (एसईएल) पर आधारित 'लिब्रे' (Libre) नामक पाठ्यक्रम विकसित किया गया है।
- यह पाठ्यक्रम चार महत्त्वपूर्ण दक्षताओं के विकास पर आधारित है, जिनमें महत्त्वपूर्ण पूछताछ (Critical Inquiry), सचेतन (Mindfulness), समानुभूति (Empathy) और करुणा (Compassion) शामिल हैं।
- ध्यातव्य है कि इस वर्ष विद्यालय आधारित इस पाठ्यक्रम के भारत और मलेशिया से शुरू होने की उम्मीद है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षणिक सशक्तीकरण और रोज़गार उन्मुख कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (Multi-sectoral Development Programme – MsDP) का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (PMJVK) के रूप में इसका पुनर्गठन किया है।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिये स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, कन्या छात्रावास, आईटीआई, कौशल विकास केंद्र आदि जैसी सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी सुविधाओं को विकसित करना है।

प्रमुख बिंदु

- पीएमजेवीके के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास से संबंधित परियोजनाओं हेतु 80 प्रतिशत संसाधनों को निर्धारित किया गया है।
- पीएमजेवीके के तहत करीब 33 से 40 प्रतिशत संसाधन विशेष तौर पर महिला केंद्रित परियोजनाओं को आवंटित किये गए हैं।
- इससे पहले केवल उन्हीं गाँवों के समूहों को इसके तहत लिया जाता था, जहाँ कम-से-कम 50 प्रतिशत आबादी अल्पसंख्यक समुदायों की होती थी। लेकिन अब आबादी के इस मानदंड को घटाकर 25 प्रतिशत कर दिया गया है, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित हो सके।

अध्याय
8

कला एवं संस्कृति (Art and Culture)

सांगली की हल्दी को मिला जीआई टैग

हाल ही में भारतीय पेटेंट कार्यालय ने महाराष्ट्र स्थित सांगली की हल्दी को ज्यॉग्राफिकल इंडेक्स (जीआई) रैकिंग प्रदान की। सांगली में हल्दी की खेती करने वाले किसान लंबे समय से 'सांगली ची हलद' यानी सांगली की हल्दी को जीआई टैग देने की मांग कर रहे थे।

जीआई टैग का लाभ

इस उपलब्धि के चलते सांगली की हल्दी को 'सांगली' ब्रांड के नाम से पूरे भारत के साथ-साथ विदेश में भी बेचा जा सकेगा। कोई भी अन्य संस्थान, कंपनी अथवा व्यक्ति 'सांगली हलद' के नाम से इसकी बिक्री नहीं कर सकेगा। इसे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में सांगली ब्रांड के नाम से पहचान प्राप्त होगी।

सांगली की हल्दी

- यह फसल यहाँ के किसानों के लिये बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- माना जाता है कि सांगली के किसानों द्वारा लगभग 200 साल पहले हल्दी के उत्पादन तथा भंडारण का एक विशिष्ट तरीका खोजा गया था।
- इस तरीके के तहत किसान हल्दी को ज़मीन के नीचे काफी गहराई में दबा देते थे, ऐसा करने से ऑक्सीजन हल्दी तक नहीं पहुँच पाती थी तथा वह शीघ्र खराब भी नहीं होती थी।
- इस तकनीक के प्रयोग से न केवल हल्दी की पैदावार में वृद्धि हुई,बल्कि इसकी गुणवत्ता तथा स्वाद में भी वृद्धि हुई जिसके कारण यह पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गई।

भौगोलिक संकेतक

भौगोलिक संकेतक (Geographical Indicator-GI) किसी उत्पाद को दिया जाने वाला एक विशेष टैग है।

- जैसा कि नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि जीआई टैग उसी उत्पाद को दिया जाता है:
  - जो किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होता है।
  - जिसमें निहित विशेषताओं का उस स्थान विशेष से गहरा संबंध होता है।
- जीआई टैग प्राप्त कुछ उत्पाद हैं- कांचीपुरम सिल्क साड़ी, अल्फांसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया इत्यादि।

भारत का 37वी वर्ल्ड हेरीटेज साइट

एक अन्य ऐतिहासिक उपलब्धि के रूप में 'मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इसेंबल्स' (Victorian and Art Deco Ensembles of Mumbai) को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरीटेज साइट्स की सूची में अंकित किया गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय बहरीन के मनामा (Manama) में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 42वें सत्र में लिया गया।

- विश्व धरोहर समिति की अनुशंसा पर इसेंबल को नया नाम 'मुंबई के विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको इसेंबल्स' दिया गया है, जिसे भारत सरकार ने भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।
- एलिफेंटा गुफाओं और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बाद यह मुंबई की तीसरी ऐसी साइट है जिसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है।
- अहमदाबाद के बाद मुंबई भारत में ऐसा दूसरा शहर बन गया है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर संपदा की सूची में अंकित है।

अध्याय
9

खेल घटनाक्रम
(Sports Events)

विंबलडन 2018

- **पुरुष एकल विजेता:** सर्बिया के नोवाक जोकोविच
- **उपविजेता:** दक्षिण अफ्रीका के केविन एंडरसन।
- **महिला एकल विजेता:** जर्मनी की एर्जेलिक कर्बेर
- **उपविजेता:** यूएसए की सेरेना विलियम्स
- **पुरुष युगल विजेता:** माइक ब्रायन व जैक सोक
- **उपविजेता:** रावेन क्लासेन व माइकल वीनस
- **महिला युगल विजेता:** बार्बोरा क्रेजिस्कोवा व कैटरिना सिनियाकोवा
- **उपविजेता:** क्वेटा पेश्के (Kveta Peschke) व निकोले मेलिचार
- **मिश्रित युगल विजेता:** एलेक्जेंडर पेया व निकोले मेलिचार
- **उपविजेता:** जेमी मरे व विक्टोरिया अजारेंका

फीफा वर्ल्ड कप 2018

- 21वें फीफा विश्वकप-2018 (Fifa World Cup–2018) का आयोजन रूस में किया गया।
- **विजेता:** फ्रांस (कप्तान हुयगो लोरिस)
- **उपविजेता:** क्रोएशिया
- बेल्जियम तीसरे स्थान पर रहा।
- 2018 के विश्वकप में आइसलैंड और पनामा ने पहली बार भाग लिया।
- यह पहला फुटबॉल विश्वकप था। जिसमें **वीडियो एसिटैंट रेफरी (वीएआर)** का इस्तेमाल किया गया।
- वर्ष 2022 का फीफा विश्वकप कतर में आयोजित होगा।
- **सर्वाधिक गोल करने वाला-गोल्डेन बूट पुरस्कार:** इंग्लैंड के हैरी केन (6 गोल)
- **सर्वश्रेष्ठ प्लेयर का गोल्डेन बॉल:** लुका मोड्रिक (क्रोएशिया)
- **फेयर प्ले अवार्ड:** स्पेन
- **सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी:** किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)
- **फीफा सिल्वर बॉल:** इडेन हजार्ड
- **फीफा ब्रॉन्ज:** एंटोनियो ग्रीजमैन
- **फीफा अध्यक्ष:** गियानी इनफैंतिनो

हिमा दास

- असम की 18 वर्षीय हिमा दास ने फिनलैंड के टेंपेरे में आईएएएफ विश्व अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं की 400 मीटर दौड़ के फाइनल में पहला स्थान हासिल किया।
- हिमा विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की ट्रैक स्पर्द्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई हैं।

अध्याय
10

बिहार सम-सामयिकी
(Bihar Current Affairs)

लालजी टंडन, बिहार के राज्यपाल नियुक्त

अगस्त, 2018 में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन को बिहार का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ये उत्तर प्रदेश राज्य से आते है। इन्होंने सत्यपाल मलिक का स्थान लिया है, जिनका स्थानांतरण अब जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल पद पर किया गया है।

बिहार सभ्यता द्वार

20 मई, 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने प्राचीन पाटलिपुत्र के गौरव का अहसास कराने के लिये पटना में सभ्यता द्वार का उद्घाटन किया। इस पर दुनिया को अहिंसा का पाठ पढ़ाने वाले जैन तीर्थकर वर्द्धमान महावीर के संदेश हैं तो वही दूसरी तरफ सारी दुनिया को प्रतीत्यसमुत्पाद और मध्यप्रतिपदा से परिचित करानेवाले बुद्ध के शांति संदेश भी हैं।

यह भव्य द्वार 32 मीटर ऊंचा और 15 मीटर व्यास वाला है।

लाल और **सफेद बलुआ पत्थर** से **इंडो-गोथीक शैली** से निर्मित इस द्वार के सबसे ऊपर चारों दिशाओं में मिश्रित धातु से शेर का प्रतीक चिह्न लगाया गया है।

नीट में टॉप करने वाली कल्पना बनी बिहार में भी सांइस टॉपर

7 जून, 2018 नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेस टेस्ट (नीट) में देश भर में टॉप करने वाली शिवहर के वाईकेजेएम कॉलेज, तरियारी की कल्पना कुमारी बिहार में भी साइंस टॉपर है।

ये बिहार के शिवहर ज़िले के नरवारा गाँव की रहने वाली हैं। कल्पना के पिता राकेश मिश्रा बिहार शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं और उनकी माँ एक शिक्षिका है।

मुख्यमंत्री बीज वहन विकास रथ

- 19 मई, 2018 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खरीफ सीजन के दौरान सरकारी योजनाओं के बारे में किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिये 'कृषि महाभियान-सह-बीज विकास वाहन रथ' को ध्वजांकित किया।
- खरीफ महाभियान-सह-महोत्सव रथ 2018 के अवसर पर पटना में एक समारोह में श्री नीतीश कुमार ने प्रत्येक ज़िले के लिये दो रथों को ध्वजांकित किया।
- दो रथों में से एक 'खरीफ महाभियान-सह-महोत्सव रथ' है जो कि खरीफ सीजन के दौरान चल रही योजनाओं के बारे में किसानों को बताने के लिये ब्लॉक, ग्राम पंचायत और गाँवों की यात्रा करेगा।
- दूसरा रथ 'बीज वाहन किसान रथ' है जिसमें खरीफ फसल के इलाज के लिये खरीफ के बीज और कीटनाशक होंगे।

मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

16 मई, 2018 को पारित कैबिनेट में अनुसूचित जाति-जनजाति (एससी-एसटी) की छात्र-छात्राओं को बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रांरभिक प्रतियोगिता परीक्षा (पीटी) पास करने पर 50-50 हजार राज्य सरकार देगी। वहीं, संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का पीटी पास करने पर इन्हें एक-एक लाख एकमुश्त दिये जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 8 मई, 2018 को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इसके लिये मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति-जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना इसी साल से लागू होगी। 16 मई, 2018 को इस योजना में अति पिछड़ा तथा पिछड़ा छात्रों को भी शामिल किया गया।

अध्याय 11

विविध (Miscellaneous)

ब्रू समुदाय को मतदान का अधिकार

गृह मंत्रालय के अनुसार, ब्रू समुदाय से संबंधित 30,000 से अधिक लोग, जो अंतर-समुदाय हिंसा (Inter–community Violence) के चलते 1997 में मिज़ोरम से त्रिपुरा चले गए थे, को जल्द ही वापस भेज दिया जाएगा। साथ ही, उन्हें मतदान का अधिकार भी दिया जाएगा। वर्तमान में त्रिपुरा के अस्थायी शिविरों में रहने वाले 5,407 परिवारों के विस्थापित लोगों को इस साल 30 सितंबर से पहले मिज़ोरम वापस भेज दिया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मिज़ोरम में इस साल चुनाव होने वाले हैं और चुनाव आयोग ने राज्य से मतदाता-सूची को संशोधित करने और उसमें विस्थापित समुदाय के सदस्यों को शामिल करने के लिये कहा है।
- रींग (Reang) जनजाति (मिज़ोरम में ब्रू के रूप में जानी जाती है), के लोगों को केंद्र, त्रिपुरा और मिज़ोरम के बीच त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये जाने के बाद मिज़ोरम वापस भेज दिया जाएगा।
- 2014 में मिज़ोरम सरकार द्वारा मतदाता सूची के आधार पर इन प्रवासियों की पहचान की गई थी। इससे पहले, छह प्रत्यावर्तन (Repatriation) योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया था और 8,573 लोगों को मिज़ोरम वापस भेजा गया था।
- इस पूरी प्रक्रिया पर दो वर्षों की अवधि में केंद्र सरकार के ₹435 करोड़ खर्च होंगे।
- त्रिपुरा सरकार के एक बयान के मुताबिक, प्रत्येक विस्थापित परिवार को सावधि जमा के रूप में ₹4 लाख की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- समुदायों के बीच संघर्ष वर्ष 1995 में तब शुरू हुआ जब राज्य में मिज़ो बहुसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों ने मांग की थी कि ब्रू समुदाय को उनके मतदान अधिकारों से वंचित कर दिया जाए, क्योंकि वे मिज़ोरम के लिये स्वदेशी नहीं हैं।

2021 के जनगणना आँकड़ों का E–संग्रहण

भारतीय रजिस्ट्रार जनरल (RGI) द्वारा अधिसूचित संशोधित नियम के मुताबिक, 2021 की जनगणना के दौरान एकत्रित आँकड़े इलेक्ट्रॉनिक रूप से संगृहीत किये जाएंगे। जनगणना से संबंधित दस्तावेज़ों का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तैयार करने के बाद, परिगणना और अन्य संबंधित कागज़ात पूरी तरह या आंशिक रूप से जनगणना निदेशक द्वारा निपटाए जाएंगे।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- अब तक 'परिगणना' (व्यक्तियों के ब्योरे वाले सारणीबद्ध प्रारूप) घरों में जाकर गणनाकारों द्वारा की जाती थी तथा इसे दिल्ली में सरकार के भंडारगृह में भौतिक रूप में संगृहीत किया जाता था।
- करोड़ों पृष्ठों वाले ये रिकॉर्ड सरकारी कार्यालय में अधिक जगह ले रहे थे, अत: अब तय किया गया है कि इन्हें इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में संगृहीत किया जाएगा।
- डेटा के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत दंडनीय अपराध होगा। RGI ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है, क्योंकि 2021 की जनगणना इसी प्रक्रिया के तहत की जाएगी।
- स्वतंत्र भारत में पहली बार 1951 में दस वर्षीय जनगणना आयोजित की गई थी।

टेक-थॉन

हाल ही में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने नई दिल्ली में पोषण अभियान के लिये टेक-थॉन का आयोजन किया। इस सेमिनार में सरकार, बहुपक्षीय संगठनों, आईटी उद्योग, यूआईडीएआई इत्यादि के विभिन्न हितधारक एकजुट हुए तथा सेमिनार में जन आंदोलन संबंधी दिशा-निर्देश जारी किये गए।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी, फ्लोचार्ट तथा मानचित्र का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- क्विक रिवीज़न हेतु प्रत्येक अध्याय में महत्त्वपूर्ण तथ्यों का संकलन।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 011-47532596, +91-8130392354, 813039235456